1	2	4	5
	(ख) रिपोर्टिंग परियोजनाओं में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या. . . .	5585	7687	10653
	(ग) कुल	180940	257700	351190
3.	**रोग प्रतिक्षण (विशेषकर उसी वित्तीय वर्ष में)**			
	(क) रिपोर्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या . . .	38	32	21*
	(ख) निम्नलिखित रोगों के लगाए गए रोग प्रतिरोधन टीकों की संख्या :			
	(1) डी.पी.टी. . .	86123	89061	30991*
	(2) डी. टी. . . .	47299	34843	1318*
	(3) बी.सी.जी . .	89279	87647	23113*
	(4) पोलियो . . .	81015	74181	29294*
	(5) खसरा . . .	उपलब्ध नहीं	56273	25228*
	(6) टी.टी. (गर्भवती महिलाएं) .	40565	58212	16386*

टिप्पणी : 1, 2, 3, 4, और 5 के सामने दिए गए आंकड़े बच्चों के हैं और जनवरी, 1989 तक के हैं।

तीरंदाजी के खेल के स्तर को सुधारने के लिये कदम

298. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खेल संगठनों को सुचारू और प्रभावी रूप से चलाने के लिए 1975 में दिशा-निर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि गत चालीस वर्षों के दौरान तीरंदाजी के विकास में भारतीय तीरंदाजी संघ का योगदान नगण्य रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और देश में खिलाड़ियों को आधुनिक तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के कार्यकाल पर सरकार ने सितम्बर 1975 में दिशानिर्देश जारी किए थे जिनके अनुसार राष्ट्रीय खेल संघ/एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष लगातार दो कार्यकालों या 8 वर्षों तक, जो भी कम हो, ऐसा कार्य संभाल सकते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय तीरंदाज अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) द्वारा देश के आदिवासी क्षेत्रों से प्राकृतिक प्रतिभाशालियों का पता लगाने के लिए 1985–86 के दौरान विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत तीरंदाजी परियोजना शुरू करने तक उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया था। इन प्रयासों के परिणाम-स्वरूप तीरंदाजी में सर्वप्रथम पदक योजना के अन्तर्गत पता लगाए तथा प्रशिक्षित किए गए श्री श्याम लाल द्वारा जनवरी 1988 में कलकत्ता में आयोजित एशियाई कप तीरंदाजी चैम्पियनशिप में जीता

गया था। इस चैम्पियनशिप में भारत ने टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता था।

1985-86 के दौरान शुरू की गई भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना का लक्ष्य देश के आदिवासी/ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों से जहां तीरंदाजी एक परम्परागत खेल माना जाता है, प्रतिभाशालियों का पता लगाना है। तत्पश्चात चुने गए प्रतिभाशालियों को आधुनिक आयातित उपस्करों सहित आवश्यक सहायता देकर वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा आधुनिक तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण हेतु दाखिला दिया जाता है तथा उनका भोजन और आवास, आधुनिक उपस्करों, किटों और ऐसे अन्य मदों पर होने वाले खर्च को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। विदेशी तीरंदाजी प्रशिक्षकों की आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए खेल नयाचार के अन्तर्गत मांग की जाती है।

Development of airports

299. SHRI GOPAL RAO, RAO: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what are the details of steps taken to develop/modernise computerise the airports of Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam, Rajhmundry, Tirupati and Cuddapali; and

(b) what are the details of the funds allocated for the above purpose, item-wise, areawise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) A statement is attached.

Statement

Details of the steps taken to develop/modernise computerise the airports at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam, Rajamundry, Tirupati and Cuddapah together with the details of funds allocated, itemwise/areawise.

S. No.	Name of the station	Details of developmental/modernisation/ computerisation scheme	Allocation made in the current year i.e. 1989-90
1	2	3	4
1	Hyderabad	*Developmental schemes*	
		(i) Commissioning of Automatic Message Switching system (Installation has since completed)	—
		(ii) Construction of new International block and car park (planned during 1989-90)	Rs. 10.00 lakhs (token provision)
		Modernisation Schemes	
		(i) Procurement and installation of Non-Directional Beacon (NDB) (Old one to be replaced)	Rs. 10.00 lakhs (token provision)